'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 15 फरवरी, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 6 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 फरवरी, 2014

जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। -गौतम बुद्ध

देश अराजकता से नहीं बल्कि संविधान से चलता है

डॉ. उदित राज

सवर्ण समाज के मध्यम वर्ग को लगा था कि फूहर, अर्धशिक्षित, देहाती, दलित, पिछड़े, उन लोगों को निर्देश देते हैं जो न केवल अपनी मातृभाषा को जानते हैं बल्कि अंग्रेजी भी बोलते हैं। तमाम विषयों की जानकारी रखने के बावजूद कानून बनाने और लागू करने की जगह पर नहीं बैठ पा रहे हैं। इनका मानना है कि जाति को इकट्ठा करके चुनाव जीत जाते हैं और फिर हुकूमत करते हैं। अब तो पैसे का निवेश करके चुनाव जीता जाने लगा है जहां पर योग्यता का कोई मतलब नहीं होता। गुस्सा और असंतोष किसी न किसी रूप में जाहिर तो होता ही है और भ्रष्टाचार एक माध्यम बना। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और जिसे समर्थन करना चाहिए लेकिन दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों का सशक्तिकरण एवं भागीदारी इस आंदोलन से कभी नहीं हो सकता। जहां संसाधनों का समुचित बंटवारा ही न हुआ हो, तो भ्रष्टाचार की लड़ाई से संसाधनहीन को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इनका फायदा निजी स्कूलों, उद्योगों एवं बाजार आदि में भागीदारी से होगा।

आम आदमी पार्टी का अब सही रूप उभर कर के आ रहा है। एक मुद्दा उठाकर मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना और फिर दूसरा खड़ा कर देना और इस तरह से पूर्व में उठायी समस्याओं का समाधान न करना बल्कि जनाधार बढ़ाने के प्रयास में हमेशा लगे रहने की सोची-समझी नीति है। दिल्ली विधानसभा में बिल पेश करने से पहले उपराज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस प्रक्रिया से गुजरे बगैर सीधा जन लोकपाल बिल जनता में रखकर के पास कराना चाहते हैं। यदि ऐसे ही सारी सरकारें करने लगी तो संविधान का क्या मतलब रह जाएगा और अंततः देश की एकता के ऊपर खतरा होना सुनिश्चित है। बड़े उद्योगपतियों के लूट का जहां तक खुलासा करने की बात है, वह अच्छी बात है लेकिन इसको मंजिल तक ले जाना चाहिए। इनकी कार्यप्रणाली आधे-अधूरे में हर चीज को छोड़ देने की है। बाबा साहेब के द्वारा निर्मित संविधान के ऊपर असर पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने से अगर थोड़ा फायदा हो रहा है तो क्षति उससे कहीं बड़ी हो रही है। जन लोकपाल बिल में आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल आरक्षण विरोधी मुहिम में शामिल रहे हैं इसलिए इनसे सावधान भी रहने की जरूरत है।

असली झाड़ू अब मैदान में

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2014। सफाई कामगार सगठनों का परिसंघ के राष्ट्रीय संरक्षक, डॉ0 उदित राज ने कहा कि जिन लोगों के हाथ में झाड़ू जन्म से ही मिल जाती है उसी झाड़ू को आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बनाकर भावुक बनाया और वोट लिया। वाल्मीकि समाज का वोट इन्हें सर्वाधिक मिला। 17 फरवरी को हजारों की संख्या में राजघाट, दिल्ली पर एकत्रित होकर दिल्ली मुख्यमंत्री का घेराव करेंगें। श्री अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति की जाएगी और अस्थाई कर्मचारियों को नियमित लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार ने कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल बड़ी ही चतुराई से अपनी पार्टी का उद्घाटन एवं प्रचार-प्रसार की शुरूआत वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि बस्ती, पंचकुइयां रोड, दिल्ली और चुनाव चिन्ह झाड़ू से किया। चूंकि वाल्मीकि समाज का झाड़ू से मानसिक लगाव है, इसलिए वे भावुक हुए और स्वतः आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। दूसरा कारण जुड़ने का यह भी था कि 'आप' ने वायदा किया था कि सफाई कर्मचारियों को न केवल नियमित किया जाएगा बल्कि उसमें ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति भी होगी। दिल्ली सरकार में 77 विभाग हैं और आयोग और विभिन्न बोर्ड आदि को भी शामिल कर दिया जाए तो लगभग 100 ऐसे विभाग एवं संस्थान हैं जहां पर कर्मचारी ठेके पर कार्यरत् हैं और अनियमित हैं। केजरीवाल कहते थे कि अन्य सरकारों से भिन्न उनकी सरकार सीधे जनता से संवाद करेगी। पहले की सरकारों से संवाद हो भी जाता था लेकिन अब इनकी सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल को भी मिलने से मना कर रही है।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि जब अन्ना हजारे 2011 में आंदोलन कर रहे थे तो उस समय अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने एक विशाल रैली के माध्यम से सवाल किया था कि क्या उनके जनलोकपाल बिल में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? जवाब नहीं मिला और अंत में हमने बहुजन लोकपाल बिल संसद की स्थाई समिति के समक्ष पेश किया और इन वर्गो के लिए आरक्षण की लोकपाल बिल में मांग की। हम श्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बिल को पास कराने की बात वे कर रहे हैं, उसमें आरक्षण का प्रावधान है या नहीं? श्री केजरीवाल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर नेता हैं और अब तो देश के सबसे बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी के खिलाफ भी

शेष पृष्ठ 6 पर...

दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में 9 फरवरी को *प्रकाशित* लेख

जाति आधारित आरक्षण की आवश्यकता

डॉ. उदित राज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, श्री जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की अवधारणा अब जातिवाद में बदल गयी है। बड़े ही आदर्शवादी समाज की उन्होंने कल्पना कर ली, जो कि है नहीं और ऐसा लगता है कि जैसे वे भारतीय समाज में रहते ही नहीं। काश! उनकी सोच समाज की सच्चाई से मेल खाती तो भारतीय समाज कितना खुशहाल और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। वे इतने अनभिज्ञ तो नहीं है कि यह नहीं जानते कि आरक्षण गरीबी मिटाने का उपाय नहीं है बल्कि निर्बल जातियों के प्रतिनिधित्व का एक संवैधानिक अधिकार है। गरीबी मिटाने की सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि उनका नाम गिनाएं तो एक लम्बी सूची बन जाएगी।

सन् 1902 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने सबसे पहले 50 प्रतिशत आरक्षण दलितों और पिछड़ों को दिया। पूना पैक्ट 1932 में हुआ उसका परिणाम यह रहा कि पहले राजनीतिक आरक्षण मिला फिर 1942 में सरकारी नौकरियों में। संविधान सभा ने आरक्षण के प्रावधान पर मंजूरी दी और यह संविधान का एक हिस्सा बन गया। द्विवेदी जी को क्या यह पता है कि 1932 या आज़ाद भारत के पहले दलितों व आदिवासियों की भागीदारी सरकारी नौकरियों और जनप्रतिनिधित्व में थी? यदि पता होता तो शायद वे ऐसा बयान न देते। जो सरकारी नौकरियां एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आज़ाद भारत के बाद है लगभग यही ब्रिटिश भारत में भी थी लेकिन जातिगत् आरक्षण न होने की वजह से इनकी भागीदारी लगभग शून्य थी।

मान भी लिया जाए कि आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दिया जाए तो आर्थिक रूप से समर्थ लोग येन-केन-प्रकारेण सबसे पहले कम आय का प्रमाण-पत्र बनवाकर गरीबों का हक मार लेगें। यह भी व्यवस्था त्रुटि रहित नहीं है। लगभग 125 करोड़ आबादी वाले देश में सरकारी नौकरियों से न तो गरीबी दूर हो सकती है और न ही एक बड़े हिस्से को रोजगार दिया जा सकता है। जहां पर आरक्षण नहीं है, वहां दलितों और पिछड़ों की भागीदारी शून्य के बराबर है। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट अखबार के पत्रकार केनेथ जे. कूपर जब नई दिल्ली में एक दलित पत्रकार से मिलना चाहे तो वे असफल रहे और वरिष्ठ पत्रकार बी.एन. उनियाल ने यह पॉयनिर अखबार में छापा। फिल्म उद्योग में भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। 1000 बड़े पूंजीपतियों की सूची अगर तैयार की जाए तो उसमें एक भी दलित-आदिवासी नहीं होगा। इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल और दैनिक अखबार हैं, उसमें से एक का भी मालिकाना हक इनके पास नहीं है। पूंजी बाजार तो जैसे इनके लिए अपरिचित वस्तु हो। शिक्षा का व्यवसायीकरण इतनी तेजी से हुआ है लेकिन उसमें इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। भवन निर्माण, दूर संचार एवं तमाम सेवा के क्षेत्र बड़ी तेजी से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हैं तो क्या इनमें दलितों-आदिवासियों की कोई भागीदारी है? जनप्रतिनिधित्व एवं सरकारी नौकरियों में अब विकास और सशक्तिकरण के अवसर नहीं के बराबर हैं, अर्थात् कितने लोगों का यहां से भला हो सकता है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। अब असली अवसर अन्य क्षेत्रों में जो कुछ उपरोक्त में वर्णित किए जा चुके हैं, उसमें हैं। यदि आरक्षण सरकारी नौकरियों एवं राजनीति में न होता तो कम से कम दलित-आदिवासी की भागीदारी तो सभी क्षेत्रों में शून्य रहती। दलित आंदोलन की मेहरबानी से मण्डल कमीशन लागू हुआ और अब पिछड़ों की भी भागीदारी सरकारी नौकरियों में होने लगी है। 1993 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो पंचम तल पर उनकी बिरादरी का केवल एक आई.ए.एस. अधिकारी था और उन्हें तब दूसरों से काम चलाना पड़ा। अब यादव एवं पिछड़े समाज के तमाम अधिकारियों से मुख्यमंत्री शासन-प्रशासन कर रहे हैं।

द्विवेदी जी की धारणा गलत है। जो जातियां आरक्षण की परिधि में नहीं हैं वे भी विकास और सिद्धांत के बजाय जाति के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं। क्यों वैश्य समाज भाजपा का बेस वोट है? जाट को आरक्षण बहुत बाद में मिला लेकिन उस पार्टी का जनाधार पहले से ही उसी जाति में क्यों था? महाराष्ट्र में मराठा को आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या वे जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं? यदि शरद पवार मराठा जाति के न होते तो क्या एनसीपी का मूलाधार मराठा जाति होती? जनार्दन द्विवेदी जी को यह सोचना चाहिए कि इस देश में कारोबार और व्यवसाय हजारों वर्ष से जाति के आधार पर ही तो होता आ रहा है।

इन्हें लगता है कि जाति के आधार पर राजनैतिक ध्रुवीकरण से विकास को धक्का लगता है। इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जब नेता बनने की प्रक्रिया ही जातीय भावना है तो उसका विकास करना दूसरी प्राथमिकता होगी। जब डॉ0 अम्बेडकर ने जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया तो उनका साथ सवर्णों ने क्यों नहीं दिया? अभी भी यदाकदा जातिविहीन समाज की स्थापना की बात दलित ही करते हैं, क्यों नहीं सवर्ण आगे आते? जिस दिन

शेष पृष्ठ 3 पर...

हमारा कोई अस्तित्व नहीं

एस. एल. सागर

'वॉयस ऑफ बुद्धा' पाक्षिक के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक डॉ. उदित राज ने पत्र के अंक–25, 16–30 नवंबर, 2013 में वेदना व्यक्त करते हुए दलित समाज के सामने यह प्रश्न रखा कि क्या हमारा भी अस्तित्व है? 'हमारा' से उनका आशय दलित समाज से है जिसकी आबादी भारत में 30 (एससी 20+एसटी 10= 30) प्रतिशत है। यह 30 प्रतिशत का समुदाय समाज में घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार आज भी है जबकि भारत को अपने संविधान के अनुरूप सत्ता चलाते 65 वर्ष से अधिक समय बीत गया है। लगता नहीं कि यह भारत की एक तिहाई आबादी का समाज अपना कोई अस्तित्व स्थापित कर पाया है। यह पूरे घृणित समाज के लिए चिंता का विषय है।

संपादक महोदय की वेदना यह है कि अभी पांच राज्यों की विधान सभाओं में विभिन्न दलों द्वारा प्रचार तक में इस समाज की उपस्थिति का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न उनसे मत प्राप्त करने के लिए अपने चुनावी एजेंडे में कोई उनके हित की निष्ठा व्यक्त की गई जैसे आरक्षित कोटे को पूरा करने, बैकलॉग भरने, उनके लिए शिक्षा रोजगार की समुचित व्यवस्था करने और उन्हें विकसित आर्थिक पायदान पर खड़े करना आदि। डॉ. उदित राज ने दलित समाज के सामने यह सीधा प्रश्न खड़ा कर दिया कि हमारा अस्तित्व अभी तक समाज में क्यों स्वीकार्य नहीं है। अभी पांच राज्यों में सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दल भागीदारी कर रहे थे पर किसी भी दल ने दलित समाज का अस्तित्व स्वीकार कर उसके हितार्थ कोई घोषणा नहीं की और इतना ही नहीं बल्कि उसकी चर्चा तक अपने चुनावी अभियान में नहीं की। डॉ. उदित राज का यह कथन भी सच्चाई के अति निकट है कि यदि ऐसा किसी अन्य प्रजातांत्रिक देश में होता और इतनी बड़ी संख्या को उपेक्षा का शिकार बनाया जाता तो वहां विद्रोह खड़ा हो जाता।

मैं समझता हूं कि दलित समाज के लिए ऐसी स्थिति गहन चिंतन और घोर चिंता का विषय है। सोचने की बात यह है कि कांग्रेस ने 2004 में आरक्षण कानून बनाने वाला विधेयक संसद में रखा जो अबतक न तो चर्चा के लिए पेश किया गया और न ही पास किया गया। प्रोन्नति में आरक्षण का बिल भी संसद में लंबित है। चुनाव वाले पांच राज्यों–दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में दलितों की जनसंख्या एक–तिहाई है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो यह 40 प्रतिशत से भी ऊपर है। इन राज्यों में भी चुनाव अभियान के दौरान किसी राजनीतिक दल ने दलितों से यह कहकर वोट नहीं मांगा कि चुनाव में उनका समर्थन करे और हमारा दल चुनाव के बाद दलित हितार्थ लंबित पड़े कानूनों को पास कराएगा।

डॉ. उदित राज का यह कथन कि मीडिया में समाचार पत्र और टेलीविजन दोनों सम्मिलित हैं पर हम देखते हैं कि इनमें संप्रदाय और जातीय उपद्रव, दंगे, दंगों में हत्याओं की चर्चाओं के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार और भ्रष्टाचार संबंधी स्कैंडल छपते रहते हैं और दलितों के संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं होती है। उनकी यह भी वेदना है कि दलितों ने न तो इस दलित विरोधी मनुवादी मीडिया का विरोध किया न अपना मीडिया पैदा करने का प्रयास किया। यह निकम्मापन दलित समाज के लिए अत्यंत खेदजनक है। इसके लिए डॉ. उदित राज का चिंतन निश्चित ही चिंताजनक है। उन्होंने दलित समाज को उठ खड़े होने का आह्वान भी किया है। किंतु यहां यह चिंतन करने की इससे भी अधिक आवश्यकता है कि जिनके उपेक्षा और तिरस्कार के हम शिकार हैं, ऐसा करना तो उनकी संस्कृति का हिस्सा है पर क्या हम स्वयं अपनी उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार और जिल्लत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? हम यह जानते हैं कि जो डरता है उसे डराया जाता है, जो पिटता है उसे ही पीटा जाता है किंतु जब कोई सीना तानकर मुकाबला करने को खड़ा हो जाता है तब उसे न कोई डराता है न पीटता है। पराजय स्वयं की कमजोरी अधिक होती है दूसरों की मजबूती से। हम अपनी अस्तित्वहीनता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और मेरे विचार से इसके दो प्रमुख कारण हैं– 1. स्वयं हमारी अज्ञानता और 2. गद्दारी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पत्रकार परिषद के अध्यक्ष श्री काटजू का कथन है कि हमारे देश में 100 में 90 मूर्ख हैं अर्थात् ये मूर्ख वे लोग हैं जो स्वविवेक की क्षमता नहीं रखते हैं अर्थात् किस परिस्थिति में क्या किया जाए का निर्णय नहीं कर पाते हैं, उन्हें झूठ–सच का विवेक भी नहीं होता है और वे अपना कौन, पराया कौन का निर्णय करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। इन 10 प्रतिशत में 5 प्रतिशत अपने को अप्प दीपो भव कहते हैं पर वे भी स्वयं अभी तक ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं। यह मनुवादी जान का शिकार है और कुछ अंबेडकर के वैज्ञानिक सोचवादी विचारधारा से कोसों दूर है। विवेकहीनता उनको पथ भ्रष्ट करती है।

दलितों का जो शिक्षित तबका है वह घोर स्वार्थी और अवसरवादी है। अपने हितार्थ हेतु पूरे समाज के साथ गद्दारी करता है और अनर्गल सूत्र गढ़ता है। इन शिक्षित लोगों में नौकरी करने वाला कर्मचारी, राजनैतिक नेता और बुद्धिजीवी आता है। नौकरीवाला स्वार्थी है, वे जहां द्विजों के साथ नौकरी करता है वहीं उनके आचरण की प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाता है। वे ऊंचे दिखने वाले निवास में रहने की जुगाड़ करता रहता है और अपने सामाजिक दायित्वों को छोड़कर उसी में लगा रहता है। वे अब जीवं सुखम् जीवेत में मस्त हैं। वे उसके पीछे पूरे अशिक्षा और दरिद्रता में नरकीय जीवन–बसर कर रहा है। उसका ही समाज, उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणवादी पूजा–पाठ में बढ़–चढ़कर भाग लेता है ताकि द्विजों की दृष्टि में पक्का धार्मिक होने का सिक्का जमाए रखें। हमारा अनपढ़, देहाती समाज इस नौकरी पेशावाले को शिक्षित और ज्ञानी समझ उसका अनुसरण करता है। जब यह पढ़ा–लिखा, पाखंडी और स्वार्थी होगा तो अनपढ़ समाज उसी जैसा आचरण करेगा।

दूसरा तबका राजनीतिज्ञों का है। राजनीति में झूठ, कपट, स्वार्थ, दगा सबकुछ चलता है। इसमें ऊपर पहुंचने के लिए गुलामी का मक्खन भी प्रयोग में किया जाता है। अब तक दलित राजनीति में निष्ठावान नेता कम और दलाल–चमचा अधिक पनपे हैं। राजनीति सब तालों की चाबी कहने वाले कांशीराम जैसे लोग और उनकी पार्टी राजनीति में सफलता पाने के बाद एक भी ताला नहीं खोल सके और दलितों में अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे एक भी रोग दूर नहीं हुआ बल्कि बसपा का हाल हमने देखा कि बजाय दलितों की कोई समस्या हल करने के वे अपनी कुर्सी बचाने के लालच में ब्राह्मणवादियों के पोषण में लग गए। इतना ही नहीं वे नारा लगाने लगे– ''हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म, विष्णु, महेश है'' और ''ब्राह्मण शंख बजाएगा–हाथी दिल्ली जाएगा''। वे यह भूल गए हैं कि दूसरों की धर्म–संस्कृति रीति–रिवाज और परंपरा को अपना कर गुलाम राजा बनने से अच्छा है अपनी धर्म संस्कृति के साथ जीने वाला समाज सेवक।

अभी 2013 में पांच विधान सभाओं के जो चुनाव हुए उसमें हमारा अस्तित्व किसी ने नहीं स्वीकारा न उनके एजेंडे में हम कहीं रहे। इसका कारण कोई और नहीं बसपा जैसा राजनैतिक दल है। हमारा समाज उसका गुलाम समर्थक बन गया और दूसरे दलों के लिए वह व्यर्थ का जीव रह गया। इसका बुरा परिणाम यह निकला कि बसपा नेतृत्व ने यह जानकर कि दलित अब जाएगा ही कहां, इसे किसी के लायक रखा ही नहीं गया है। अब ब्राह्मणवादियों को जोड़ा रखा जाए ताकि अपनी कुर्सी सलामत बनी रहे। दूसरे दलों ने दलितों को इसलिए नकार दिया क्योंकि उन्होंने इसे बसपा का गुलाम समझ लिया। यही कारण था कि किसी दल के घोषणा पत्र में दलितों की कहीं कोई चर्चा नहीं थी।

यह सच है कि बाबा साहेब ने कहा था कि हमें शासक भी बनना है किंतु यह कभी नहीं कहा था कि गुलाम शासक बनना और अपने से शक्ति पाकर अपनों की उपेक्षा कर सवर्णों का हित साधक बनना। यूपी में बसपा द्वारा बाबा साहेब की नीति का वास्ता देया गया किंतु उस नीति को उसी बसपा ने श्मशान घाट पहुंचा दिया। आरक्षण के कारण जो अन्य दलों ने दलितों को स्थान दिया। उन्होंने गूंगे, बहरे और मूक लोगों को ही चूना जो पशु की भांति पेट भरकर भुनभुनाते रहे पर दलितों की ओर से मुंह फेर लिया और पार्टी आकाओं की वन्दना करते रहे।

यदि हम बुद्धिजीवियों की बात करें तो हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि दलित समाज में जो शारीरिक श्रम की कमाई न खाकर बुद्धि के बल से कमाते और खाते हैं, उन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता है। बुद्धिजीवी बुद्धि के साथ जीते हैं, नहीं कहा जा सकता पर वे बुद्धि को खाते हैं, यह बात सच है। नौकरी पेशा और अन्य पढ़ा–लिखा बुद्धिजीवी इस अर्थ में है क्योंकि वे श्रम का न खाकर बुद्धि का खाता है पर वह सही अर्थों में न बुद्धिजीवी है न बुद्धिमान। एक बात समझने की जरूरत और है कि पुस्तक–पत्रिकाएं और पत्र जिनमें पढ़ने की चाह नहीं है, वे पढ़े–लिखे हो सकते हैं बुद्धिजीवी नहीं, यह बात कहीं तक सर्वथा युक्ति संगत है।

यह बात चुनावों तक ही सीमित नहीं है। चुनाव घोषणा पत्रों में किसी राजनैतिक दल द्वारा दलितों की बात नहीं कही गयी है। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी किसी दल के घोषणा पत्र में दलितों के आरक्षण, उनका शिक्षा और आर्थिक हित की चर्चा कहीं नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि किसी भी दल द्वारा दलितों का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। स्मरण रहे कि किसी समाज की ऐसी दशा दो परिस्थितियों में होती है। एक तो यह कि वह समाज ऐसा हो जो मूल्यांकनहीन हो अर्थात् जिसकी स्थिति ऐसी हो जिसके सहयोग का मिलने न मिलने से कोई प्रभाव न पड़ता हो। दूसरी स्थिति यह है कि वह समाज गिनती में किसी की जय–पराजय को प्रभावित तो करती हो पर ऐसा समाज एक का ऐसा दास हो कि दूसरे उस पर विश्वास न करते हो। तीसरी स्थिति यह है कि किसी समाज की न कोई विचारधारा हो न एक विचारधारा पर संगठित हो। ऐसा समाज दूसरों के लिए अस्तित्वहीन हो जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्थिति यह स्पष्ट है कि दलित समाज किसी राज्य से संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है और स्थानीय स्तर पर जहां जिसके दबाव में है, वे उसी को डाल देता है। जब यह वहां किसी एक का है ही नहीं तो कोई भी उसके अस्तित्व को क्यों अहमियत देगा। यूपी का दलित बसपा से चिपका है, दूसरे दल यही मानकर यहां दलितों के अस्तित्व उनके लिए कुछ है, इसे मानने को तैयार नहीं है।

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि दलितों का कहीं कोई दल अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है। राजनीति में अस्तित्व स्वीकार कराने के लिए किसी भी समाज में संगठन हों। दूसरे वह संगठन स्वतंत्र हो अर्थात् किसी को स्वीकारने और किसी को खारिज करने को स्वतंत्र है अर्थात् वह किसी दल का बंधुआ न हो। जैसे उत्तर प्रदेश सहित भारत का मुसलमान संगठित है और वह उसी को वोट देता है जो उसकी हर बात सुने और उनके अधिकारों का संरक्षण करें। दलित समाज का अस्तित्व कायम हो सकता है यदि वह संगठित हो और सामूहिक विवेक का प्रयोग करें।

यहां यह बात भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जिन्दा कौमें कभी अस्तित्वहीन नहीं होती है जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं और विजय पाते हैं, उनका अस्तित्व स्वतः स्थापित हो जाता है। आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रायः विभिन्न वर्ग और संप्रदाय अपने अधिकारों की मांग को लेकर जब सड़कों पर उतर आते हैं तो उनकी ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित होता है। ऐसे समाज का अस्तित्व दल स्वीकारता है और सरकार ही नहीं हर व्यक्ति को ऐसे संघर्षशील समाज का अस्तित्व हर वर्ग स्वीकार करता है और जब किसी जाति वर्ग का अस्तित्व स्वीकार हो जाता है तो उसकी हर मांग हर दल स्वीकारने लगता है।

दलितों का अस्तित्व स्थापित हो और उनके अधिकारों का मूल्यांकन होने लगे, उसके लिए उन्हें जो कुछ आवश्यक है वह कलमकारों, विचारकों और राजनैतिक ईमानदार चिंतकों से मिलता है यदि ये अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें। कलमकारों की बात करें तो वे ही कलमकार सही मार्गदर्शन कर सकते हैं जो धर्मांधता की रतौंधी से मुक्त है। नेत्र दोषी दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। कुछ कलमकार भ्रामक सोच का सृजन कर रहे हैं। इनके भटकाव में दलित डूबने के सिवाय कोई अस्तित्व कायम नहीं कर सकते हैं। देखने में आया है कि तमाम दलितों के अखबार पाखंड परोसते हैं। वे दलितों में भ्रम फैलाने का प्रकाशन करते हैं। हिमायती के संपादक सुमनाक्षर अंबेडकर और वैज्ञानिक चिंतन की बात करते हैं और हिंदुओं के महाकुंभ की प्रशस्ति स्थापित करते हैं और रैदास ने पैर से पत्थर हटाकर जमीन से गंगा निकाल दी जो राजा के पीछे–पीछे चल दी (हिमायतीः दिसंबर, 13)। इसी अंक में ये गुमराह करते हैं कि 1851 का सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो कि बकवास है। 1857 में भारत से अंग्रेज जाएं, यह लड़ाई नहीं लड़ी गई और न ही स्वतंत्रता की मांग की गई। यह कुछ धर्मांधों का ग्रंथ था जो बैरकपुर छावनी में शुरू हुआ था। यह किसी प्रकार से जन आंदोलन की मांग नहीं थी। राजा किले मांग रहे थे और उनमें बने रहने की मांग कर रहे थे। लक्ष्मीबाई मात्र झांसी मांग रही थी। उस समय देश में मुसलमान हिंदू राज्यों के शासक थे। यदि तब अंग्रेज चले गए होते तो दिल्ली पर बादशाह जफर होते और हिंदू राज्यों में राजा। ऐसी सत्ता में तो दलित गुलाम ही होते और उनके गले में हांडी तथा कमर में झाड़ू होता। ऐसे कलमकार पूरे दलित समाज को भटकाव में डाल देंगे। हमारा कलमकार विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए, पाखंड से बहूत दूर।

दलित अस्तित्व के लिए राजनीति में भागीदारी आवश्यक है किंतु हमारी एक नीति होनी चाहिए जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को वरण करती हो। हमारी राजनीति को नीति का अनुसरण करना चाहिए न कि राजनीति को सब तालों की चाबी कहकर नीति के ऊपर स्थापित करना चाहिए। अब तक जिन राजनैतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ में राजनीति को ऊपर रखा, उन्होंने अपना निजी हित साधा और पूरे दलित समाज को पीछे धकेला है। हमारे राजनीतिज्ञ बाबा साहेब का अनुसरण करें जिन्होंने दलित अस्मिता के लिए पद छोड़ा था जो राजनेता पद के लिए दलितों को पीछे धकेलकर छोड़ देते हैं, वे गलत हैं।

मैं आगाह करना चाहूंगा कि दलित समाज घोर अंधकार में है। उसे मनु युग में धकेलने का प्लान चल रहा है और इसके नेता, रहनुमा, चिंतक, संघर्ष नायक सभी नींद में हैं, इन्हें जागना होगा। मनुवादियों ने बाबा साहेब के संविधान को पूर्ण विफल कर दिया है। लोकतंत्र केवल ऊपर से दिखाई देता है। विधानसभा और लोकसभा का सदस्य स्वतंत्र मतदान से नहीं चुना जाता है। लोकतंत्र मर चुका है जिसमें दलित आवाज सुनी जाती थी। कोई भी सरकार अब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान का अस्पृश्यता निरोधक अनु. 17 और आरक्षण देने वाला अनु. 335 प्रभावहीन बनाकर व्यर्थ कर दिए गए हैं। जाल तैयार किया जा रहा है ताकि दलित उच्च एक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान न कर सके और सरकार के कार्य–कलापों में हिस्सेदारी न कर सकें। धन–धर्म दोनों पर डकैती डाली जा रही है। अब तो इच्छा से धर्म भी ग्रहण नहीं कर सकते। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाकर अनुच्छेद 25 को ध्वस्त कर दिया गया है। सत्ता चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की, दलितों के लिए दोनों जहरीली है। एक सांप नाथ है तो दूसरी नागनाथ। एक खुला नाग है तो दूसरा आस्तीन का सांप। मैं देश की 80 फीसदी आबादी वाले मूल निवासी समाज को एक मंच पर होना अनिवार्य मानता है अन्यथा अगर न चेते तो मिट जाओगे तब इनका अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देगा।

दैनिक समाचार पत्र 'पंजाब केसरी' में 14 फरवरी को *प्रकाशित लेख*

भारतीय भेदभाव में सबसे आगे

डॉ. उदित राज

खिड़की एक्सटेंशन, दिल्ली की ओर देश के बहुत लोगों की नजरें है कि क्यों दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती अश्वेत औरतों के घर पर छापा मारा, क्यों नहीं पुलिस ने उनकी सुनी, क्या यह छापा कानूनी था आदि-आदि सवाल उठे हुए हैं। वहां के लोग अफ्रीकियों से परेशान नजर आते हैं और यह बात 26 जनवरी को आईबीएन 7 के वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष द्वारा वहां पर चर्चा करते हुए देखकर के पता लगता है। वहां के ज्यादातर लोगों का कहना था कि अफ्रीकी लोग सेक्स और नशीले पदार्थ में लिप्त हैं। देश का प्रबुद्ध वर्ग कानून मंत्री के इस कृत्य से नाराज है। कानूनी तौर से रात में किसी के घर छापा नहीं मारा जा सकता जब तक कि विशेष परिस्थिति न हो और उसे कानून करने की इजाजत देता हो। भारती जी 15 जनवरी को मीडिया के साथ देर रात में वहां पहुंचे, पुलिस भी बुला लिया और आदेश दिया कि छापा मारो। पुलिस कानून के अनुसार काम की और उनके धमकी में नहीं आई। इस घटना के कई पहलू हैं जिस पर न लोगों की बोलने की हिम्मत होती है और न ही लिखते हैं। मैंने पूरी दुनिया देखी है, स्वयं के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जितना भारतीय भेदभाव करते हैं उतना कोई और नहीं।

अश्वेत लोगों को ज्यादातर लोग हबसी कहते हैं। नफरत की दृष्टि से भी देखते हैं और जब वे सड़कों पर गुजरते हैं तो गंदी-गंदी टिप्पणियां होती है। प्रश्न उठता है कि यह भेदभाव करने वाली मानसिकता क्या अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पैदा हुए? हीन भावना के वजह से ये धारणाएं है या और कारण है। अश्वेतों का अमरीका या यूरोपीय देश 17वीं और 18वीं शताब्दी में खरीद-फरोख्त करते थे। इंग्लैंड पार्लियामेंट के सदस्य विल्बर फोर्स, एक कट्टर ईसाई थे, ने पूरी जिंदगी अश्वेतों के दासता की मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहे और अंततः 1833 में कानून बन सका। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इन्हें मुक्त कराया परिणामस्वरूप इनकी हत्या 1865 में कर दी गयी। हम इनके साथ भेदभाव क्या इसलिए करते हैं कि अंग्रेजों ने हीन भावना का उत्पात हममें की या इनके

साथ विदेशियों ने भेदभाव किए। आंशिक रूप से यह एक सत्य हो सकता है लेकिन स्वाभाविक रूप से हम प्राचीन काल से ही एक-दूसरे के साथ भेदभाव करते रहे हैं। जाति के आधार पर भेदभाव और रंग के आधार पर अलग-अलग हो सकता है लेकिन कहीं न कहीं उसी मानसिकता का यह अभिव्यक्ति है। हमारे वेदों और पुराणों में गोरा और सांवला की बात बहुत प्रमुखता के साथ हुई है। भगवान शिव का जब वर्णन होता है तब यह भी कहा जाता है कि वह श्याम रंग के थे। जहां किसी के गुण की बात हो तो क्या यह जरूरी है बताना कि उनका रंग गोरा था या काला। भगवान कृष्ण के बारे में यही कहा जाता था कि उनका रंग श्यामल था। अफ्रीकी लोगों को यह नहीं पता कि भारतीय उन्हीं के साथ नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ में भी भेदभाव खूब करते हैं। अगर लड़की गोरी हो और उसका नाक-नक्शा भी सुडौल हो तो वैसे ही घरवालों की चिंता आधी हो जाती है कि कन्यादान में मुश्किल नहीं होगी। इसी समाज में इंसान का दान भी होता है? श्यामली लड़की हो तो ज्यादा दहेज का इंतजाम तो करना ही पड़ता है साथ ही साथ यह जरूरी नहीं है कि अच्छा लड़का मिले। फेसबूक पर लड़कियों के बारे में तमाम टिप्पणियां आती रहती है। एक दिन एक टिप्पणी मैंने देखा कि गोरी और सुंदर लड़की हो तो उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जानती है कि कोई गधा इंजीनियर, डॉक्टर, आईआरएस, आईएएस आदि बनने के लिए मेहनत कर रहा होगा। जब मैंने 1989 में भारतीय राजस्व सेवा की ट्रेनिंग करने गया तब इसका अनुभव काफी गहराई से हुआ। तमाम ब्यूरोक्रेट्स या जो अच्छी नौकरियों में हैं उन्हें गोरी और सुंदर लड़की चाहिए चाहे दहेज कम ही मिले, पैसा तो वैसे ही कमा लेंगे। मेरा बाल्यकाल गांव में बीता और अनुभव किया है कि यदि कोई व्यक्ति काना है तो गांव के ज्यादातर लोग सुबह उसका मुंह देखने से कतराते हैं इस सोच के साथ कि कहीं दिन न खराब हो जाए। जिस महिला को बच्चे नहीं होते उसके भी दर्शन से प्रातःकाल बचते हैं ताकि उनका दिन अच्छा बीते। क्या इतना भी क्रूर समाज कहीं और हो सकता है कि अंधा और बिना बच्चे की स्त्री अपने विरह से खुद झुलस रहे हैं और उसपर समाज का यह अत्याचार। यदि इस प्रकार के भेदभाव का पता यहां रह रहे युगांडा, नाईजीरिया और कांगो के लोगों को लग जाए तो शायद उनकी पीड़ा कम हो जाए। किम बैरिंगटन नारीसेटी अर्बन क्रेयान प्रेस की प्रकाशक का लेख 25 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि जब वे दिल्ली में थी तो एक 8 वर्ष के बच्चे ने जोर से पत्थर मारा और चश्मा न पहनी होती तो आंख फूट जाती, उनके भारतीय पति ने पकड़ा तो उसने कहा कि इसलिए किया कि उसने सोचा कि वह अफ्रीकी है। जरा सोचिए कि एक बच्चे में इतना भेदभाव की भावना है, क्या और किसी समाज में ऐसा संभव है? उनका अनुभव था कि जैसे वह अजीब वस्तु हों और जहां भी जाती थी लोग अजीब तरीके से देखते थे। शिक्षित लोग भी यही करते हैं। कोई भी अफ्रीकी लड़की हो, हमारे सेक्स के भूखे लोग इन सभी को सेक्स वर्कर ही समझते हैं।

इस सच को झुठला नहीं सकता कि भारतीयों से ज्यादा कोई भेदभाव नहीं करता। भारतीय समाज लगभग 6700 जातियों में बंटा हुआ है और प्राचीन भारत से एक ही समाज में रह रहे हैं। जहां तक इनके रंग की बात है उसमें मिश्रण है अर्थात् किसी भी जाति में गोरे और सांवले मिल जाएंगे। अमेरिका में गोरे और काले भिन्न हैं और वे 17वीं-18वीं सदी से ही साथ रहना शुरू किए। अश्वेत जानवरों की तरह खरीदे और बेचे भी जाते थे लेकिन उन समाजों ने बहुत जल्द ही भेदभाव खत्म करने का कार्य किया है। सन् 2010 में अमेरीका में 20,96,000 शादियां हुई थी और उसमें से 2,75,500 अंतर समुदाय में हुई जिसमें से 1,92,850 काले और गोरों के बीच में। वर्तमान में वहां पर 8.5 प्रतिशत अंतर समुदाय शादियां हुई है जबकि 1980 में यह 3.2 प्रतिशत थी। हमारी आबादी सवा सौ करोड़ है उसके अनुपात में कितनी अंतरजातियां शादी हो रही है, यह सभी जानते हैं, अभी भी अपवाद ही है। अतः प्राचीन भारत से लेकर अब तक हमसे ज्यादा भेदभाव करने वाला दुनिया में कोई और समाज नहीं है।

सागरिका घोष और कुछ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बहुत ही मुश्किल का समय रहा जब खिड़की एक्सटेंशन के लोगों के साथ चर्चा हो रही थी। वहां के ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे अश्वेतों से परेशान हैं और पुलिस कुछ करती नहीं इसलिए कानून मंत्री ने सही कार्य किया। सागरिका घोष ने बहुत ही माकूल सवाल किया कि आपकी शिकायत यही है कि अफ्रीकी लड़कियां पूरी रात आती-जाती रहती हैं तो इसका जवाब नहीं मिला। जिस दिन कानून मंत्री उनके घर पर छापा मारा तो उस समय भी कोई सेक्स और नशीले पदार्थ का धंधा होते नहीं मिला। उनके मेडिकल में भी ऐसा नहीं आया। ये नहीं जानते हैं कि दूसरे समाज में प्राचीन काल से ही मर्द और पुरुष अलग नहीं रहे हैं अतः उन्होंने स्वाभाविक जिंदगी गुजारी है और यहां पर पराए मर्द से बात करना या देर रात आना, चरित्रहीनता है। बेचारी अश्वेत लड़कियों को यह नहीं पता था। यहां का पुरुष जब बाहर के देशों में जाता है तो क्या-क्या नहीं करता लेकिन अपने समाज में कुछ और ही होता है। खिड़की एक्सटेंशन के लोग अपनी अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता की आजादी से तो वंचित ही हैं और चाहते हैं कि अश्वेत लड़की भी उसी तरह रहे। दओस में इस घटना के ऊपर अफ्रीकी युनियन ने बहुत ही नाराजगी प्रकट की है और चेतावनी दी है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वह इसे उठाएंगी।

कुछ भी न करो तो ...

देश में आरक्षण विरोधी एवं जातिवादी ताकतों की सक्रियता को देखकर कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम सप्ताह में पांच ऐसे लोग, जो अंबेडकरवादी और मिशनरी हैं, का नाम, पता व मोबाइल नंबर 56767 पर एसएमएस करें। 160 अक्षर (Character) से ज्यादा का एसएमएस नहीं भेजा सकता है। एसएमएस में सबसे पहले UR टाइप करें उसके बाद SPACE देकर नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आदि दें। मोबाइल नंबर का होना ज्यादा जरूरी है और ईमेल हो तो उसे भी भेजें।

परिसंघ और समर्थक यदि इतना छोटा सा भी काम कर लें तो हमारे पास लाखों सही लोगों का मोबाइल नंबर आ जाएगा और जब भी चाहेंगे तो उन्हें अपने आंदोलन या आवश्यक सूचना एसएमएस के द्वारा सूचित करते रहेंगे। पूरा पता आ जाए तो और भी अच्छा है। यदि कई लोगों का साथ भेजना हो तो कम से कम नाम, जिला, प्रदेश और मोबाइल एसएमएस करें। इस तरह से एक से ज्यादा लोगों का डिटेल एक ही एसएमएस में आ जाएगा। भेजने के लिए सामने का उदाहरण को गौर से पढ़ें-

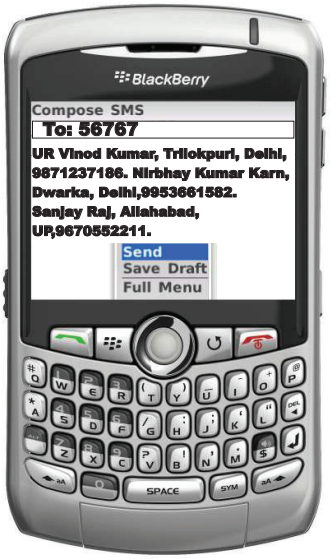

(Note- UR के बाद एक स्पेस अवश्य छोड़ें)

शेष पृष्ठ 1 का...

जाति आधारित आरक्षण की आवश्यकता

समान शिक्षा और अंतर्जातीय विवाह वाला समाज हो जाएगा, हम आरक्षण स्वयं छोड़ देगें। क्यों नहीं द्विवेदी जी इस आंदोलन में हमारा साथ देते? तमिलनाडु में आरक्षण 69 प्रतिशत् है लेकिन उत्तर भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा हर क्षेत्र में विकसित राज्य है। लोगों को आरक्षण से घबराना नहीं चाहिए अब तो अमेरिका जैसे देश भी आंतरिक कलह समाप्त करने के लिए हर क्षेत्र में वहां के अश्वेतों, हिस्पेनिस एवं मूलनिवासियों को भागीदारी दे रहे हैं।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

आक्रोश का कवि

तरुण विजय

विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश जब सीमा से गुजर जाए तो कलम की आग्नेयता नामदेव ढसाल बन जाती है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा रचा, जिसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया। किसी को बख्शा नहीं और उन्होंने यहां तक सुना-सहा कि तुम्हारी कलम जहर उगलती है, तुम हमारे समाज, हमारे धर्म के खिलाफ हो। नामदेव ढसाल ने कभी किसी की परवाह नहीं की। जो सब कुछ दांव पर लगा देता हो उसे किसका डर सता सकता है? वे अनेक लोगों, अनेक समुदायों और संगठनों, विचारधाराओं और बहुधा तीखी विषाक्तता के साथ सौमनस्य के ताने-बाने पर चोट करने वालों के साथ खड़े भी दिखे। पर उन्होंने कभी अपने मन और कलम के साथ समझौता नहीं किया।

उनके अवसान पर हमें क्यों दुःखी होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वे न केवल हमारे रक्तबंधु, हमारे बहुत अपने, संवेदनशील भारतीय थे, बल्कि उन्होंने दर्द को जीया और इस हद तक जीया कि वे खुद उसी दर्द में ढल गए। उनकी कविताएं, उनका रहना, खाना-पीना, उनका व्यवहार और गुस्से में तमतमाते हुए कविता पाठ, मुर्दों को भी हिला देता था, क्योंकि उसमें कुछ भी तथाकथित भद्रजनों क चौखटें में ढली शालीनता को स्वीकार नहीं करता था।

हमारे इर्द-गिर्द इतना अधिक पाखंड और दोहरापन व्याप्त हो गया है कि हमें अन्याय के आक्रोश में बदलने वाले रूप को स्वीकार करने में दिक्कत होती है। हम यह मानना चाहते हैं कि चूंकि हमने या हमारे पूर्वजों ने कभी मैला नहीं ढोया, कभी साहब लोगों की गंदगी अपने हाथों से, अपने झाड़ू से साफ नहीं की, कभी पर्याप्त दूरी बनाते हुए एक हाथ से छोड़ी जाने वाली बासी और दूसरों की थाली में बची जूठी रोटियां अपने दोनों हाथों का पत्तल बना कर ठक से नहीं बोचीं (हाथों में पकड़ी), कभी सड़क पर झाड़ू उस समय नहीं लगाया, जब हमें देख कर अच्छे, ऊंचे, बड़ी जाति वाले नाक पर दुपट्टा या रूमाल रख कर हमसे एक-दो मीटर की दूरी यों बनाते हुए गुजरते हों मानों हम बीमारी का गंद टपकाते जानवर हों, तो सारे लोग हमारे ही स्तर की क्षमता, मानसिक आत्मविश्वास और कुलीन लोगों के बीच संवाद की भद्रता रखते होंगे।

इसीलिए इन भद्र, कुलीन, श्वेत या रक्तवर्णी चंदन से सुशोभित भव्य मस्तक वाले, बिरहमन और ठाकुरों को समरसता की बात करना बड़ा सुहाता है। किसी धर्मग्रंथ में भेदभाव नहीं है- वे कहे जाते हैं। मनुस्मृति में नहीं है, रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। ठीक है। अगर किसी में भी नहीं है, कभी किसी ने ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा नहीं, तो नामदेव ढसाल को पैदा होने की जरुरत क्यों हुई?

हमारा व्यवहार अपने आप को धोखा देने वाला है। हम यह जानते हुए भी उसी धोखे में जीते रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे हम सब की दुकान चलती रहती है। नामदेव ढसाल खराब लिखते थे, बेहद तोड़ने वाली भाषा में लिखते थे, वह सब लिखते थे, जो समरसता की चादर तार-तार करने वाला है- वे हमारी सभ्यता, संस्कृति, वगैरह के खिलाफ थे, यह सब कहने का क्या अर्थ है? ऐसी समरसता जो सौ प्रतिशत एक ही बिरादरी और जाति का समर्थन करे, तो क्या करें उसे पूज कर? नामदेव ढसाल की बातों से सहमत होने का दंभ न भरते हुए भी उनका प्रशंसक होने की कोशिश की जानी चाहिए। यह बड़ा कठिन है।

'गोलपीठ', 'मूर्ख महात्रैयाण्ये', माओवादी विचारों से तथाकथित जोशीली प्रेरणा का दावा करने वाली 'तुझी इयत्ता कंची', इंदिरा गांधी के बारे में 'प्रियदर्शिनी', बेहद विवादास्पद खेल और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन और दलित विचार के समाजवादी चिंतन पर 'आबेडकरी चलवल' और 'अंधोले शतक' अगर अनेक अतिरेकी विचारों के कारण चर्चित संग्रह रहे, तो 'भी मारले सूर्याचा रथाचे सात घोड़े' (मैंने सूरज के रथ के सात घोड़े मारे) जैसी कृतियां सामान्य वंचित वर्ग के गहराते दर्द को समेटे हुए अद्भुत कविता है, जो अपार जनप्रिय हुई।

64 वर्ष की आयु में उन्हें जाना नहीं था। लेकिन असहमति में उठे हाथ अधिक लंबा सफर तय नहीं कर पाते। उन्होंने मराठी साहित्य के आकाश को बदल डाला और विद्रोह और विरोध की कविता का ऐसा लावा बहाया कि कविता का रूप बदल गया। उनकी कविताएं जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी भाषाओं में भी अनूदित हुई। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने अग्निपथ का नायकत्व ओढ़ लिया था। ब्लैक पैंथर से लेकर इंडियन रिपब्लिकन पार्टी तक वे आक्रोश के जनकवि बने रहे।

उनकी मराठी कविताओं का कहीं हिंदी अनुवाद आया होगा, शायद। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। मूल मराठी में ही कुछ पढ़ा। मेरे मित्र थे मुंबई में शरद चव्हाण जो मजदूर विषयों पर महाराष्ट्र टाइम्स में स्तंभ लिखते थे और दलित मुद्दों पर हमसे बहुत चर्चा होती थी। तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते जनजातीय क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यकर्ता था। जो भेदभाव, कटुता, विद्वेष और घनीभूत घृणा दलितों के प्रति देखने को मिलती थी, वही अनुसूचित जनजातियों के प्रति भी जिंदा थी। उसे केवल देख कर, जीकर ही महसूस किया जा सकता है। लेकिन हमारे बीच सब वे कार्यकर्ता थे, जो तथाकथित सजातीय या बड़ी जाति के कहे जाते थे और वे अपना घर, परिवार, डिग्री और पदवी छोड़ कर जनजातीय समाज की सेवा के लिए जुटे हुए थे।

हममें भी बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा होता था, जब अफसरी और नेताओं के हृदयहीन व्यवहार को देखते थे। अगर सजातीय अफसर है तो हो सकता है कि जातीय घृणा से वह भेदभाव का बर्ताव करता हो। लेकि बहुधा अनुसूचित जाति और जनजाति के अफसरों और नेताओं को भी अपने ही समाज के विरुद्ध काम करते हुए उनका सजातियों की ही तरह शोषण करते हुए देखते तो अजीब लगता था। शायद अपना जातीय स्तर ऊंचा करने का एक तरीका यह भी है कि जिन्हें हम निम्न जाति का कहते हैं उनके प्रति वही शोषक दृष्टि अपना ली जाए, जो बड़े लोगों में देखने को मिलती है।

पर हमें नामदेव ढसाल के गुस्से के प्रति आकर्षण और मोह होते हुए भी खुद न गुस्सा करना था और न ही तीखे तेजाब में डूबे शब्दों से प्रहार करना था। जाति विलीन हो जाएगी, तो जाति भेद भी विलीन हो जाएगा। पंगत में कोई किसी की जाति न पूछे तो जाति की पहचान ही कहां रहेगी। अगर मन मिल जाए तो घृणा भी दूर हो सकती है। पर यह लंबा रास्ता है और ऐसे किसी मामले

में शार्टकट होता नहीं।

हम चाहे जितना अपने मन को पाक-साफ करने-बताने की कोशिश करें, पर बद्धमूल पूर्वग्रह बड़े कठोर हैं। हमारे मित्रों की सूची में, शादी-ब्याह, तेरहवीं पर भेजे जाने वाले पत्रों की पता सूची में, समाज के बहुसंख्यक दलित/वंचित वे जिन्हें हम जाति में अपने बराबर नहीं मानते, होते ही कितने हैं। या सही तो यह कहना होगा कि होते ही नहीं। फिर भी भी हमें अच्छा लगता है कि नामदेव ढसाल के तीखेपन पर चोट करें और कहें कि नहीं, नहीं, नहीं, रास्ता सरलता, मिष्टभाषिता और नामालूम-सी दिखने वाली पद्धति से होकर गुजरता है। हो सकता है यह भी सही हो, लेकिन सच तो यह है कि जाति का भेदभाव और घनीभूत घृणा हो गई नहीं। नामदेव ढसाल का स्मरण अगर इस घृणा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सम्मति के लिए आवश्यक अग्नि पैदा कर सके तो यही नामदेव होने की सार्थकता को सिद्ध करेगा।

(साभार : जनसत्ता)

मल उठाने का 'आध्यात्मिक अनुभव'

सुभाष गाताडे

क्या मल उठाने या गटर साफ करने के काम को - जिसने लाखों लोगों को बेहद अपमानजनक स्थितियों में पीढ़ी दर पीढ़ी ढकेला है -आध्यात्मिक अनुभव कहा जा सकता है? निश्चित ही नहीं, यह अलग बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो इन दिनों प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर देश के अलग हिस्सों में भ्रमण कर रहे हैं, इस मसले पर बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। दरअसल जब से मोदी ने अपनी अलग छवि गढ़ने के लिए पहले शौचालय, फिर देवालय की बात कही है, और गुजरात में इस समस्या से निपटने का दावा किया है, तबसे न केवल इस मसले पर उनके विचारों की भी विवेचना चल रही है बल्कि यह बात भी सामने आ रही है कि सैनिटेशन की समस्या को अपने राय में समाप्त करने का दावा करनेवाले गुजरात की स्थिति इस मामले में कितनी फीसड्डी है।

लेकिन पहले गटर साफ करने को आध्यात्मिक अनुभव की श्रेणी में रखने की बात करनेवाले मोदी के विचारों पर गौर करें। अपनी किताब कर्मयोग में वह लिखते हैं - मैं नहीं मानता कि वे (सफाई कामगार) इस काम को महज जीवन-यापन के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को नहीं किया होता ..किसी वक्त उन्हें यह प्रबोधान हुआ होगा कि वाल्मिकी समुदाय का काम है कि समूचे समाज की खुशी के लिए काम करना, इस काम को उन्हें भगवान ने सौंपा है और सफाई का यह काम आन्तरिक आध्यात्मिक गतिविधि के तौर पर जारी रहना चाहिए। इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि उनके पूर्वजों के पास अन्य कोई उद्यम करने का विकल्प नहीं रहा होगा। (पेज 48-49)

मालूम हो कि इस किताब का प्रकाशन 2007 में हुआ था, जिसमें आई ए एस अधिकारियों के चिन्तन शिविरों में मोदी द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन किया गया है। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन जैसे अग्रणी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के सहयोग से इसकी पांच हजार प्रतियां छापी गयी थीं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार राजीव शाह के चलते ही इस बात का खुलासा हुआ था।

जाति प्रथा एवं वर्णाश्रम की अमानवीयता को औचित्य प्रदान करने वाला उपरोक्त संविधानद्रोही वक्तव्य 'टाईम्स आफ इण्डिया' में नवम्बर मध्य 2007 में प्रकाशित भी हुआ था। आप इसे गुजरात के दलितों के एक हिस्से के हिन्दुत्वकरण का परिणाम कहें कि गुजरात में इस वक्तव्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मगर जब तमिलनाडु में यह समाचार छपा तो वहां दलितों ने इस बात के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए जिसमें मैला ढोने को 'आध्यात्मिक अनुभव' की संज्ञा दी गयी थी। उन्होंने जगह-जगह मोदी के पुतलों का दहन किया। अपनी वर्ण मानसिकता के उजागर होने के खतरे को देखते हुए जनाब मोदी ने इस किताब की पांच हजार कापियां बाजार से वापस मंगवा लीं, मगर अपनी राय नहीं बदली। वर्ष 2009 में सफाई कर्मचारियों की एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने उनके काम को मंदिर के पुरोहित के काम के समकक्ष रखा था। उन्होंने कहा - जिस तरह पूजा के पहले पुजारी मन्दिर को साफ करता है, आप भी मन्दिर की ही तरह शहर को साफ करते हैं।

अब 'पहले शौचालय और बाद में देवालय' की बात पर गौर करें। एक युवा सम्मेलन में मोदी की टिप्पणी ने केसरिया पलटन की अपनी दरारों को खूब उजागर किया। शिवसेना की तरफ से कहा गया कि- अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस नरेन्द्र मोदी को अपनी शौचालय परियोजना का ब्राण्ड एम्बेसडर बना दे तो मोदी के परिवार के तोगडिया ने उन्हें हिन्दूविरोधी घोषित किया। वैसे आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 2001 की जनगणना ने ग्रामीण सैनिटेशन की हकीकत को जिनमें तीनों बुनियादी सुविधाएं - पीने का पानी, बिजली और सैनिटेशन - उपलब्ध है, उसका प्रतिशत महज 21 फीसदी बताया था, जबकि 2012-13 की इंडिया रूरल डेवलपमेण्ट रिपोर्ट बताती है कि यह अब गुजरात की 25 फीसदी ग्रामीण आबादी तक पहुंच सका है। शहरी इलाकों में भी स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है।

मानव गरिमा नामक एक समुदाय आधारित संगठन, जो सफाई कामगार समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, उसके द्वारा हाल में सम्पन्न अध्ययन में यह बात उजागर हुई थी कि अहमदाबाद के अन्दर 126 ऐसे स्थल है, जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन की बाकायदा निगरानी में मानवीय श्रम द्वारा मल उठाने का काम बदस्तूर जारी है।

गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार के कथन और वास्तविक जमीनी हकीकत में गहरा अन्तराल दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर इसी संगठन ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास याचिका डाली थी, तब गुजरात सरकार को बेहिचक यह कहने में संकोच नहीं हुआ था कि वह 1993 में बने अधिनियम एम्प्लायामेन्ट आफ मैनुअल स्केवेंजर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन आफ ड्राई लैटरिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रति संकल्पबद्ध है, जिसके अन्तर्गत ऐसा काम करने वाले को अलग पगार दी जाती है। गुजरात सरकार की तरफ से यह बात भी अदालत को बतायी गयी थी कि उनके यहां ऐसी स्थिति नहीं है।

यह जानना समीचीन होगा कि हाथों से मल उठाने की परम्परा का आज भी जीवित रहना क्या राज्य में इस वजह से विद्यमान है क्योंकि राज्य के कर्णधार इस मसले पर बेहद प्रतिक्रियावादी तरीके से सोचते हैं। खासकर जनाब मोदी मल उठाने के काम को आध्यात्मिक अनुभव का दर्जा देते हैं, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। वैसे जिस राज्य के कर्णधार जब खुद ऐसे दलितद्रोही चिन्तन से लैस हों, तब इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि 21 वीं सदी की दूसरी दहाई में भी सूबे में इतने बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता क्यों व्याप्त है?इस सम्बन्ध में दलित मानवाधिकारों के लिए कार्यरत संस्था नवसर्जन द्वारा 1,589 गांवों के विस्तृत अध्ययन पर प्रकाशित रिपोर्ट (2010) बताती है कि इनमें से 98 फीसदी गांवों में आज भी अस्पृश्यता का बोलबाला है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दलित अत्याचारों के मामले निपटाने के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता होती है, मगर जहां तक राज्य सरकार का सवाल है तो वह इसे न स्थापित करने के लिए संसाधानों की कमी का रोना रोती रहती है।

गौरतलब है कि दलित अत्याचार के सन्दर्भ में राज्य सरकार एवं उसके यशस्वी प्रशासक के चिन्तन को जानना हो तो हम राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन रिपोर्ट इम्पैक्ट आफ कास्ट डिसिमिनेशन एण्ड डिस्टिन्क्शन्स आन इव्ल आपर्चुनिटीज : ए स्टडी आफ गुजरात (मई 2013) को भी देख सकते हैं जिसमें वह निःसंकोच जातिगत भेदभाव को परसेप्शन अर्थात अनुभूति का मसला मानती है। (साभार : देशबंधु)

दैनिक समाचार पत्र 'पंजाब केसरी' में 7 फरवरी को *प्रकाशित लेख*

आरक्षण से भारतीय समाज मजबूत हुआ है न कि कमजोर

डॉ. उदित राज

कांग्रेस के नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए न कि जाति के आधार पर। काश भारत का समाज आर्थिक आधार पर चला होता तो आज दुनिया में यह महाशक्ति होता। सबसे ज्यादा लोग कुपोषण के यहीं न होते। लिंग अनुपात में इतना असंतुलन न भी होता। दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे, कोढ़ी, लंगड़े, भीखमंगे क्या यहीं होते ? हजारों वर्ष तक देश गुलाम न होता। आतंकवाद के गतिविधियों का केंद्र भारत न होता। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं यहां क्यों होती ?

द्विवेदी जी को अपने समाज से पहले संपर्क कर लेना चाहिए कि क्या वह आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए तैयार हैं ? जब जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर कामकाज और पेशा तय हो जाएगा तो ब्राह्मण को भी मलमूत्र सिर पर ढोना पड़ेगा। मान लिया जाय कि अमीर सवर्ण को ऐसा कृत्य करने की जरूरत नहीं पड़ती तो गरीब को जरूर करना पड़ेगा वरना शौचालय, नाली, सड़क आदि को साफ कौन करेगा ? अब कुछ लोग कहने लगें हैं कि सवर्ण भी सफाई के पेशे में आने लगे हैं लेकिन असलियत यह है कि वेतन तो लेते हैं परंतु काम दलितों से ही कराते हैं। अपवाद से समाज नहीं चलता। क्या कपड़ा धोने का काम कर सकेंगे ? क्या मरे हुए जानवर को उठाना, चमड़ा निकालकर के पकाना और फिर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, क्या ऐसा कर सकेंगे ? सुअर पालन, मुर्गी पालन आदि फिर इन्हें भी करना पड़ेगा ? खैर करें कि द्विवेदी जी का समाज आरक्षण देकर के देश के सारे अन्य क्षेत्रों के ऊपर आधिपत्य जमा लिया है। दलितों-आदिवासियों की भागीदारी राजनीति एवं सरकारी नौकरियों में ही है। दलित आंदोलन की वजह से ही पिछड़ों को आरक्षण मिला और अब उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। सरकारी नौकरियों में अभी तक कोटा पूरा नहीं किया जा सका है। पिछले वर्ष के आंकड़े के अनुसार, भारत सरकार के 149 सचिव में से एक भी दलित नहीं था।

द्विवेदी जी को भली-भांति पता होगा कि गरीब दलित और गरीब सवर्ण तो रोटी-बेटी का संबंध क्या करेंगे ? अमीर दलित से भी उतना दूरी है अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए। गरीब सवर्ण ज्यादा जातिवादी होता है क्योंकि उसकी शिक्षा और समझदारी उतनी नहीं होती। कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता श्री जगजीवन राम जब बनारस में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया तो दूसरे दिन उसे गंगाजल से नहलवायी गई। कौन नहीं जानता कि बाबू जगजीवन राम बड़े शक्तिशाली देश के नेता रहे हैं। आर्थिक आधार पर यदि मान-सम्मान और यहां तक कि व्यापार आदि का निर्धारण होता तो उससे अच्छा और क्या हो सकता।

आधुनिकता के चकाचौंध में द्विवेदी जी को लगता है कि जाति खत्म हो रही है तो उनकी ये सोच गलत है। जब यह देश बाहरी हमलावरों से बार-बार पराजित होता रहा है तो भी सवर्णों ने आहावन नहीं किया कि चलो अब जाति को मिटाकर के अपने घर को दुरुस्त करें। जब इतनी बड़ी जरूरत और मजबूरी समाज को एक होने की थी तो उस समय जाति नहीं टूटी तो अब आसानी से इसे कैसे खत्म किया जा सकता है ? सन् 1757 में लॉर्ड क्लाइव केवल 540 ब्रिटिश इंफेंटरी, 600 रॉयल नेवी सेलर्स, 800 सिपाही और 14 फील्ड गन के ही सहयोग से कलकत्ता को फतह कर लिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि पूर्व में भी

चंद फौज के साथ जो हमलावर आए, देश पर आसानी से राज करते गए।

जो भी समाज विभाजित है वह कमजोर रहेगा ही। आजादी के बाद देश गुलाम नहीं हुआ और न हो ही सकता है। अतीत में इसलिए होता रहा कि 6700 से अधिक जातियों के अलग-अलग जन्म के आधार पर पेशे थे। केवल क्षत्रिय को देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। आबादी के हिसाब से एक जाति न केवल शासन-प्रशासन करने में छोटी थी बल्कि बाहरी हमलावरों को रोकने में भी असफल। अन्य जातियों में वह भावना ही नहीं थी कि देश उनका है बल्कि दलितों और पिछड़ों को सवर्ण समाज में अपनी सेवा के लिए तैनात किया करता था। अब शासन-प्रशासनन में लगभग सभी जातियों की भागीदारी है तो सभी को लगता है कि देश हमारा है। द्विवेदी जी के सोच के अनुसार, इनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। यदि विभिन्न वर्गों के भागीदारी के ऊपर असर पड़ता है तो देश की एकता और अखंडता के ऊपर असर जरूर पड़ेगा।

आधुनिक भारत के बड़े शहरों के युवक-युवतियां आरक्षण से बड़ा नफरत करते हैं। वे सोचते हैं कि इससे मेरिट पर समझौता हो रहा है और अंततः देश की उन्नति प्रभावित हो रही है। आधुनिकता के चकाचौंध में समाज की सच्चाई से वे रूबरू नहीं हैं। यह भी कहा जा सकता है कि घर से संस्कार इनको इस तरह मिले हैं कि आरक्षण से उनके अवसर मर रहे हैं। घरवाले यह क्यों नहीं बताते कि आजादी के पहले भारत एक भी युद्ध नहीं जीता, उन दिनों तो आरक्षण नहीं था। इन युवाओं की सोच से दलितों और पिछड़ों पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है और न चाहकर के भी वे अपने ही जाति को नेता मानते हैं चाहे वह जितना भी भ्रष्ट व निकम्मा हो। किसी भी अखबार के वैवाहिक पृष्ठ को देखकर के समाज के बारे में जानना मुश्किल नहीं है कि अभी भी यह कहां खड़ा हुआ है। जाति से शादी-विवाह, परिवार, बच्चे और आने वाली पीढ़ी तय हो रहे हैं। क्या इससे कोई बड़ी सच्चाई हो सकती है ? मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है कि कोई व्यक्ति गलत आदत का शिकार लंबे समय तक हो तो अंततः उसे वह सही मानने लगता है। सवर्ण युवा और युवतियां भी इसी सोच के शिकार हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के अपेक्षा समान शिक्षा, रोजगार एवं जातिविहीन समाज की लड़ाई जरूरी है। क्या उन्होंने कभी सोचा कि उनके मां-बाप जब वे पढ़ रहे थे तो सुबह उन्हें नहला-धुलाकर के स्कूल के लिए तैयार करते थे लेकिन भारत में एक समाज ऐसा है जिनके मां-बाप सुबह 5 बजे झाड़ू लेकर के शौचालय, नाली एवं सड़क की सफाई करने निकल जाते हैं। काम पर से लौटते भी दोपहर में हैं तो उनके बच्चों को कौन स्कूल भेजने के लिए तैयार करता होगा ?

दलित और पिछड़े जाति समाप्त करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे लेकिन क्या सवर्ण इसके लिए सहमत होंगे ? निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से शिक्षा, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में तमाम अवसर पैदा हुए हैं, क्या दलितों की भागीदारी वहां नाममात्र की भी है ? यदि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं हुआ होता तो सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी नहीं के बराबर होती और पूर्व की तरह गुलाम की जिंदगी जी रहे होते।

जनार्दन द्विवेदी जी अपना वक्तव्य वापिस लें- डॉ. उदित राज

सी. एल. मौर्य

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014। डा0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता, श्री जनार्दन द्विवेदी ने जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या अब वह कांग्रेस नहीं रही जो नेहरू जी और गांधी जी के समय में थी, जब आरक्षण मिला था ? संविधान बनाते समय संविधान निर्माण सभा में लंबी बहस के बाद सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था। संविधान सभा के पहले भी अंग्रेजी हूकूमत ने जाति के आधार पर आरक्षण दिया था। क्या श्री जनार्दन द्विवेदी समाज के बारे में अंग्रेजों के बराबर भी समझ नहीं रखते हैं जो बाहर से आकर राज किए ? इसी सोच की वजह से देश हजारों वर्षों तक गुलाम था और ऐसी सोच रही तो फिर से कमजोर होगा। डा0 उदित राज ने कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी एवं उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी से मांग की कि वे तुरन्त कहें कि श्री जनार्दन द्विवेदी अपने वक्तव्य को वापिस लें। आजादी के इतने दिन बीत गए आरक्षण पूरा लागू ही नहीं हुआ और उल्टा खत्म करने की बात तो बहुत ही पीड़ादायक है।

डा0 उदित राज ने आगे कहा कि पहले का अघोषित आरक्षण पहले खत्म हो उसके बाद राजनैतिक एवं सरकारी नौकरियों में मिले संवैधानिक आरक्षण पर सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या जन्म के आधार पर मल-मूत्र धोने और उठाने का आरक्षण एक विशेष जाति को नहीं दिया गया है ? क्या जन्म के आधार पर एक विशेष जाति को कपड़ा धोने, मरे हुए जानवर को उठाने, चमड़ा निकालने आदि का काम नहीं दिया गया है ? यह आरक्षण आर्थिक आधार पर तो नहीं बल्कि जाति के आधार पर है। क्या जनार्दन द्विवेदी जी इन जातियों का पेशा अपनी जाति से अदला-बदली कर सकते हैं ? क्या अपवाद को छोड़कर जाति में ही शादी-विवाह नहीं होते हैं ? शादी-विवाह के अभाव में परिवार और आने वाली पीढ़ी की कल्पना नहीं की जा सकती। जब पूरा समाज ही जातिगत ढ़ांचे पर चल रहा है तो आरक्षण के क्षेत्र में ही आर्थिक मापदंड की बात क्यों की जा रही है ? यदि आज के जनार्दन द्विवेदी

पूजा-पाठ और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें आरक्षण की भी देन है। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर कांग्रेस के धुरविरोधी थे फिर भी गांधीजी ने ही उन्हें संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी। संविधान में आरक्षण जैसे प्रावधान समाहित किए गए, इसी कारण दलित, आदिवासी कांग्रेस का वोटबैंक बना वरना कांग्रेस अब तक देश से खत्म हो चुकी होती। उ0प्र0 में दलित वोटबैंक खिसकने से कांग्रेस की क्या हालत हुई, कौन नहीं जानता ?

डा0 उदित राज ने आगे कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करने वालों को यह भी जान लेना चाहिए कि दर्जनों अवसर के क्षेत्र हैं लेकिन दलित-आदिवासी की भागीदारी आरक्षण की वजह से केवल राजनीति व सरकारी नौकरियों में मिली है। इन तमाम क्षेत्रों, जैसे- भवन निर्माण, ठेका, मीडिया, उद्योग, टेलीकाम, कला एवं संस्कृति, फिल्म, पूंजी बाजार, शेयर, बाजार, ट्रेड, शिक्षा, आयात-निर्यात में क्या दलितों व आदिवासियों की कोई भागीदारी है ?जनार्दन द्विवेदी जी सर्वे करके पता लगा लें तो पाएंगें कि दलितों व आदिवासियों की इन क्षेत्रों में भागीदारी लगभग शून्य ही होगी। उनसे मांग की जाती है कि वे अपने वक्तव्य का खंडन करें।

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of '**Justice Publications**' at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

सेना में आरक्षण के लिए धरना

मदन राम

गत् 7 फरवरी को अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज के नेतृत्व में पटना के आर. ब्लॉक चौराहे पर निजी क्षेत्रों के साथ न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण की मांग को लेकर एकदिवसीय धरना दिया गया। दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूलमाला के साथ श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए धरना का शुभारंभ किया गया।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज अपने ओजपूर्ण तथा प्रभावशाली संबोधन में 'आरक्षण बचाओ' और 'आर्थिक सत्ता में भागीदारी' पर बल देते हुए कहा कि दलितों-पिछड़ों को उसका अपना अधिकार आसानी से मिलने वाला नहीं है, इसके लिए संगठित होकर संघर्ष करना ही होगा। बिहार में 11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक की मांगें पूरी नहीं हो जाती। साथ ही टोला सेवक, विश्वास मित्र तथा सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग बिहार सरकार से की।

धरना की अध्यक्षता करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन राम ने मंच संचालन की जिम्मदारी नवादा जिलाध्यक्ष रघुनंदन चौधरी, प्रधानाध्यापक को सौंपी। अपने स्वागत भाषण में मदन राम ने परिसंघ द्वारा उठायी गयी 11 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे पूरा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आग्रह किया और मांग पत्र सौंपा।

इनकी मांगें निम्नलिखित हैं :-

1. निजी क्षेत्र के साथ-साथ न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण।
2. एक राज्य का जाति प्रमाण पत्र सभी राज्यों में मान्य हो।
3. विशेष अभियान के तहत नौकरियों में हमारी खाली जगह (बैकलॉग) को जल्द से जल्द भरा जाय विशेषकर सफाई कर्मचारियों की शीघ्र बहाली तथा स्थायी किया जाए।
4. भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में कोई भी स्थायी निदेशक पदस्थापित नहीं है। जो पदाधिकारी पदस्थापित होता है वह हमारे वर्ग का नहीं होता है, इसे दूर किया जाए।
5. सभी मुख्यालयों पर अंबेडकर जयंती राजकीय समारोह के रूप में राजकीय सम्मान के साथ मनाया जाय।
6. राज्य सभा एवं विधान परिषद में हमारा प्रतिनिधि भेजा जाए।
7. उच्च शिक्षण संस्थानों में भी हमारी भागीदारी नहीं के बराबर है। हमारी भागीदारी सुनिश्चित किया जाय। जैसे :-विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज शिक्षकों की बहाली शीघ्र किया जाए।
8. हमारे वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए जैसे :-झूठे मुकदमें में फंसाना, वेतन काटना एवं रोकना, छुट्टी नहीं देना, निलंबित करना, गोपनीय रिपोर्ट खराब कर प्रमोशन में बाधा डालना, समय पर पेंशन का निर्धारण नहीं करना, आदि किसी भी तरीकों से परेशान करने वाले अधिकारियों को कानून बनाकर दंडित किया जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
9. सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्राप्त सभागारों, जैसे- कृष्णा मेमोरियल हॉल, रविंद्र भवन, पटना तथा जिला मुख्यालयों से सहायता प्राप्त भवन को हमारे सम्मेलन के लिए निःशुल्क आवंटित किया जाय।
10. प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों के बच्चे/बच्चियों को सरकारी छात्रवृत्ति अग्रिम तौर पर देकर पढ़ाई की व्यवस्था की जाए।
11. 'टोला सेवक' और 'विकास मित्र' को स्थायी किया जाए।

अरूण चौधरी, ओम प्रकाश, आनंद कुमार, आशीष रजक, देवचंद राम, शिवधर पासवान सहित अन्य साथियों ने अपनी बात लोगों तक रखी और सरकार से आग्रह किया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें।

धरना में राज्य सचिव धीरेंद्र प्रताप, आनंद कुमार, रामेश्वर रजक, राजकुमार पासवान, नंद जी राम, अजय कुमार एडवोकेट, राहुल कुमार, रघुनाथ प्रसाद, मायारानी, संत बेलास राम, रविंद्र रजक, शैलेंद्र सिंह, छोटन चौधरी, सुनील रजक, राजकुमार, रामनारायण मेहता, अनिल पासवान, जयमंगल प्रसाद, रामेश्वर राम आदि ने भाग लिया।

शेष पृष्ठ 1 का...

असली झाड़ू अब मैदान में

भ्रष्टाचार का अरोप ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि केस भी दर्ज कराया है। क्या वे अभी भी अपने जन लोकपाल बिल में उद्योगपतियों के भ्रष्टाचार को शामिल कर रहे हैं अथवा नहीं ? सन् 2011 में भी हमने उनसे कहा था और जब उन्होंने नहीं किया तो हमने अपने बहुजन लोकपाल बिल में शामिल किया था। यदि केजरीवाल जी उद्योगजगत् को अपने जनलोकपाल बिल में शामिल नहीं करते हैं तो यह दोहरी नीति होगी। अभी तक उनके जनलोकपाल बिल की प्रति किसी को मिली नहीं है और जिस तरह से पास कराना चाहते हैं, वह गैर संवैधानिक है। जहां तक संविधान के पालन की बात है, उससे ज्यादा जरूरी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए लेकिन अराजकता और असंवैधानिक कृत्य के माध्यम से नहीं वरना देश टूटने का खतरा है। उस स्थिति में भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा और देश को तमाम और कीमतें चुकानी पड़ेगीं।

श्री विनोद कुमार ने कहा कि दिल्ली के कोने-कोने से दिल्ली प्रदेश के सफाई के काम से जुड़े विभिन्न संगठनों के नेताओं के नेतृत्व में हजारों लोग 17 फरवरी, 2014 को 11 बजे राजघाट, नई दिल्ली पर एकत्रित होगें और वहां से दिल्ली सचिवालय तक मार्च करते हुए मुख्यमंत्री का घेराव करेगें।

0999504477
पर मिस काल करें

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अजा/जजा परिसंघ

यदि आप जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना के पक्षधर हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक भागीदारी के समर्थक हैं और अजा/जजा परिसंघ तथा इससे जुड़ी नवीनतम गतिविधियों की जानकारी चाहते है तो नीचे लिखे नम्बर पर मिस काल करें और कम से कम 10 साथियों को भी ऐसा करने के लिए कहें

0999504477

Rest of Page 8...

NECESSITY OF CASTE-BASED RESERVATION

In other words, it is not difficult to know as to how many people can benefit from these reservations. Now the real scope is in other sectors as mentioned above. Had reservation been not there in Government jobs and legislatures, the share of governance of Dalits and Adivasis in all the sectors would have been very negligible. Because of Dalit struggle, Mandal Commission came into existence and reservation of Government jobs for Backwards was also introduced. When Mulayam Singh became Chief Minister in 1993, there was only one I.A.S. officer of Yadav caste on 5th floor and he had to manage with officers from other castes. Now, the Chief Minister is running the administration with the help of officers from Yadav and other backward castes.

Dwivedi Ji's concept is wrong. Even the people of the castes which are not under the purview of reservation , they are also doing politics on the basis of caste rather than on the basis of development and principles. Jats have got reservation quite late and yet they form base vote for RLD and INLO lead by jat leaders. Even when Marathas are not getting any caste-based reservation, are they not doing politics on the basis of Maratha vote bank. Had Sharad Pawar not been a Maratha, could Marathas become the vote bank of NCP. Janardan Dwivedi Ji should realize that the basis of occupation and businesses have been caste for thousands of years.

Dwivedi thinks that caste-based political polarization adversely affects development. Caste base politics relegates development and it is natural because votes are polled on the basis of sentiment. Why did the upper caste people not support Dr. Ambedkar when he advocated for the establishment of a casteless society? Even now it is only Dalits who talk occasionally about casteless society but the upper caste people do not come forward on this issue. The day equal education for all and inter-caste marriages are introduced in the society, we shall forgo reservation. There is 69% reservation in Tamil Nadu but it is the most developed State in all areas as compared to all North Indian States. People should not be afraid of reservation. Now even in countries like America, to end internal conflicts, there is reservation for Non-Whites, Hespians and aborigines.

INDIA IS A FRONTRUNNER IN DISCRIMINATION

Dr. Udit Raj

The Khirki Extension incident in Delhi has attracted attention of the people across the country. People are asking as to why Delhi Police did not take action when the Law Minister of the State raided the houses of non-white African women. Questions are being asked about the legality of the raid by the Law Minister. The local residents are said to be fed up with the Africans living in the area and this thing became evident on the 26th January,2014, during a discussion with the Senior Journalist of IBN 7. Most of the local residents are of the view that the Africans are involved in sex and drug rackets. The intelligentsia of the country is critical of the approach of the Law Minister to this issue. Strictly speaking, no house should be raided in the night unless there are special circumstances and has the approval of the lawful authority. Bhartiji reached the spot along with media and called for the Police force also and advised them to raid the premises. Police acted according to law by not succumbing to the unlawful orders of the Law Minister. There are several aspects to this issue on which people do not have the courage to speak or write. I have seen the whole of the world and based on my personal experience I can say with confidence that the level of discrimination as is prevalent in India is not practiced anywhere else in the world.

Non-whites in India are called Habshis (Niggers). They are looked down upon by the people when they move on the Indian roads and highly offensive remarks are passed against them. A question arises whether such a mindset of the Indians has been inherited from the British when they ruled India. This is because of the inferiority complex which is the main reason for our mindset. In America and Europe, blacks were traded as slaves in the 17th and 188th centuries. Bilver Force, a British MP who was a staunch Christian fought all his life for the emancipation of the non-whites and finally in the year 1833, a law against slavery was made. The famous American President, Abraham Lincoln, abolished slavery and as a result he was assassinated in 1865. Do we discriminate against the non-whites because the Britishers inculcated a sense of inferiority complex in us or just because the people of other countries discriminated against them. Partially it could be true but by nature we Indians have been practising discrimination against one another since times immemorial. Discrimination could be on the basis of caste and apartheid but the present behaviour of the Indians on this issue is because of the same mind-set. In our Vedas and Puranas also, the issue of white and non-white has been discussed in great detail. Whenever there is a mention of Lord Shiva, it is said that he had a dark complexion. When we are extolling the virtues of someone, is it essential to mention that the person concerned is white or dark. About Lord Krishna also, it is said that he had a dark complexion. Africans are not aware of the fact that do not only discriminate against them based on their complexion but also they do against their own people who have dark complexion. If a girl has a white complexion and has sharp features, the worries of the parents are just reduced to half on the issue of marriage. It is in this Indian society that a woman is given in charity. If a girl has a dark complexion, you have to arrange a big dowry in marriage and even then it is not sure that you will get a good boy. There are different types of comments on the Face Book about girls. In one of the tweets, it was mentioned that a fair-complexioned and beautiful girl has not to bother much for her marriage as some fool must be working hard for her to become an Engineer, Doctor, IRS, IAS etc. When in the year 1989, I went for training for the Indian Revenue Service, I had an in-depth experience of this fact. All bureaucrats or people who are holding other good positions, they need fair-complexioned and good-looking girls even if they bring less dowry because earning money is not a problem for them. I spent my childhood in a village and experienced that if somebody is one-eyed, people avoid to have a look at him as the first thing in the morning as according to them, it is not a good omen. People also avoid to see a woman who is not able to give birth to a child, for the first time in the morning as it is considered a bad omen. Can there be such a cruel society in which blind persons and women who cannot bear children, who are already victims of their disabilities, are treated so callously. If this type of discrimination comes to the notice of people from Uganda, Nigeria and Congo, etc. then perhaps their agony may be reduced to some extent. While going through an article by Kim Barrington Narisetti (Publisher, Urban Crayon Press), in the Economic Times dated 25.1.2014, in which she said that an 8-year old child who was riding on the back of a bike with his father hurled a big stone at her and had she not worn sunglasses, she would have lost her eyes. When the child was chased and caught by her brave husband, he said that he thought that the person was African. Imagine the mind-set of a child with so much of discrimination ingrained in him which is just does not seem to be possible in any other society. Her experience was that the local people thought as if she was a funny creature. Even the educated people had a similar mind-set. Our sex-starved people consider all the African girls as sex workers.

Nobdody can deny the fact that Indians are front-runners on the issue of discrimination. Indian society is divided into 6700 castes. As far as colour of the Indian people is concerned, there is a mixture of both fair and dark complexions in different castes. In America, whites and blacks are different from each other and they started living together since 17th or 18th century. Non-whites were traded as slaves like animals but those societies soon decided to abolish slavery. In the year 2010, 20,96,000 marriages took place and 2,75,500 were inter-community marriages out of which 1,92,850 marriages were between whites and blacks. Recently 8.5% marriages are inter-community marriages whereas in the year 1980, it was only 3.2%. Our population is about 1.25 billion and in that proportion the number of inter-caste marriages is very very low and it is rather an exception.

Sagarika Ghosh and other Human Rights activists had a very difficult time when the Khirki Extension issue came up for discussion with the people of the area. Most of the residents said that they were fed up with the Blacks in the area and Police was a silent spectator and as such they were quite happy with the action taken by Delhi Law Minister. Sagarika Ghosh raised a pertinent question that your only complaint is that the African girls are found on the road throughout the night to which she did not get any reply. The day on which Delhi Law Minister raided the house of the African girls, he did not find any sex or drug activity going on inside the house. Their medical examination also did not reveal any such activity. Our people are not aware that in the other society, men and women are not segregated and do not live separately and as such they lead a natural life and in our society, intermingling of women with other men and coming home late in the night amounts to characterlessness. The poor African girls were not aware of this reality of this Indian society. When Indian males go abroad, he indulges in all sorts of activities peculiar to the customs of those societies but in his own society, he is totally different. People of Khirkee Extension are devoid of their freedom of expression and independence and they want the African girls also to be deprived of this freedom. The African Union has very severely criticized the Khirki Extension incident at Davos and has threatened that this issue would be raised in UNO also.

Rest of Page 8...

It is now the real test for "JHARU"

massive rally and asked if there would be a provision for reservation for dalits, advasis, backwards and minorities in the Jan Lokpal Bill. Confederation didn't get any reply and in the end we presented Bahujan Lokpal Bill before the Standing Parliamentary Committee and urged for reservation for these communities in the Lokpal Bill. We are also in touch with Sh. Arvind Kejriwal and his associates to let us know whether there is provision for reservation for these communities in his proposed Jan Lokpal Bill. Shri Kejriwal is very shrewd and clever leader and now he has not only levelled corruption charges but has also filed an FIR against the top most capitalist of the country, Shri Mukesh Ambani. Is he still not ready to include corrupt capitalists in his Janlokpal Bill or not? In the year 2011 also we had asked him to do so. When he did not do so we had included this provision in our Bahujan Lokpal Bill. If Kejriwal doesn't include corporate houses in his proposed Jan Lokpal Bill the he would be following double standards. So far the proposed Jan Lokpal Bill has not been made public and the way he wants to get it passed is unconstitutional. The question of following the constitutional requirements is more important than launching a campaign against corruption. Undoubtedly corruption should be abolished from our country but not at the cost of anarchy and unconstitutional means which may disintegrate the country. In that case corruption will increase mani-fold for which the country will have to pay a very heavy price.

Shri Vinod Kumar said that under the leadership of different Safai Kamgar Organisations of Delhi, thousands of people are going to assemble on 17th February, 2014 at 11 AM at Rajgaht, Delhi and will march to Delhi Secretariat and gherao the Delhi Chief Minister.

Rest of Page 8...

JANARDAN DWIVEDI JI SHOULD RETRACT HIS STATEMENT : Dr. Udit Raj

professions of these castes with the profession of his own caste? Do inter-caste marriages take place barring exceptions? In the absence of inter-caste marriages, we cannot even think of inter-caste families in the future generations. When the entire society is caste-based, then why in the case of reservation, there is a demand for reservation on the basis of economic factors. If in the present time, Janardan Dwivedi is carrying out Puja rituals and getting respect in the society, it is also because of undeclared reservation. Even though Baba Saheb Dr. Ambedkar was a staunch opponent of the Congress Party, he was entrusted with the job of writing our Constitution by Gandhi Ji. It is only because of reservation in the Constitution, Dalits and Adivasis continued to be the vote bank of the Congress Party otherwise the Congress Party would have been wiped out from the country. Who does not the pitiable condition in the Congress Party in Uttar Pradesh after Dalits stopped supporting the Congress Party?

Dr. Udit Raj further said that the protagonists of reservation on economic factors said that they should not forget that there are dozens of opportunities and fields but the share of Dalits and Adivasis is only in the areas of politics and government jobs. Do Dalits and Adivasis have any share in all other areas like building industry, contracts, media, industry, telecommunication, art and culture, film industry, share marke, corporate sector, trade, education, import-export ? I request Janardan Dwivedi Ji to get a survey done in this regard and he will find that there share in these areas is very negligible. We demand that he may retract his statement.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 6 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 February, 2014

It is now the real test for "JHARU"

New Delhi, February 12, 2014. Dr. Udit Raj, Chief Patron, Confederation of Safai Kamgar Organisations, said that the same JHARU which has been the destiny of a large number of people was taken away by the Aam Admi Party as its symbol based on which they got the votes of these people. They got maximum votes of the Valmikis. On the 17th of February, 2014 a large number of people would assemble at Rajghat, Delhi and gherao the Delhi Chief Minister. Shri Arvind Kejriwal had promised that the contract system for the Safai Karmacharis would be abolished and temporary employees would be regularized but nothing has been done in this regard till date.

Shri Vinod Kumar, National Chairman, Confederation of Safai Kamgar Organisastions, said that Shri Arvind Kejriwal very cleverly inaugurated the launching of his party and its election campaign from Valmiki Mandir, Valmiki Basti, Panchkuiyan Road, Delhi and election symbol was declared as JHARU. Because the

Valmikis are intellectually attached to JHARU, they became emotional and of their own they associated themselves with this party. The other reason for their alliance with the Aam Admi Party was the promise made by the party that not only the temporary employees will be regularized but the contract system for Safai Karmacharis would be abolished. There are approximately 77 departments in Delhi Govt. and if different commissions and boards are also included then the total number of such departments and institutions would become approximately 100 where employees are working against contract and have not been regularized. Kejriwal had said that his govt. will be different from previous governments and would have a direct dialogue with the people. The earlier governments had dialogue with the people occasionally but Kejriwal's govt. is refusing to meet the people representatives in the Chief Minister's Secretariat.

Dr. Udit Raj said that when Anna Hazare launched his campaign against corruption in 2011 then the All India Confederation of SC/ST Organisations had organized a

Rest on Page-7...

JANARDAN DWIVEDI SHOULD RETRACT HIS STATEMENT : Dr. Udit Raj

New Delhi, February 4, 2014. Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations, said that the Congress Spokesperson, Shri Janardan Dwivedi has made a statement that caste-based reservation should be abolished and should instead be based on economic factors. Shall we take it that no longer it is the Congress Party of the time of Nehru Ji and Gandhi Ji when reservation was introduced? After prolonged deliberations, the Constituent Assembly resolved to give reservation based on social and educational backwardness. Even before the Constituent Assembly gave this verdict, the British rules had given reservation on the basis of caste. Does Shri Janardan Dwivedi not have even that much of knowledge about our social structure as the foreign British rulers knew. It is because of this mind-set that the country suffered from slavery for thousands of years and and if this mind-set continues, we shall become more backward. Dr. Udit Raj urged Congress President Smt. Sonia Gandhi and the Congress Vice President, Shri Rahul Gandhi to advise Shri Janardan Dwivedi to retract his statement.

Dr. Udit Raj further said that in the first instance, undeclared reservation should be abolished and after that the issue of reservation in politics and government jobs should be considered. He asked whether the jobs of scavenging and night-soil carrying, washing clothes, transportation of dead animals and leather-processing are not based on the birth of an individual? This reservation is not based on any economic factor but just on the basis of case. Is Janardan Dwivedi prepared to inter-change the

Rest on Page-7...

NECESSITY OF CASTE-BASED RESERVATION

Dr. Udit Raj

Senior Congress Party leader, Shr Janardan Dwivedi has said that reservation should be done based on economic factors after abolishing caste-based reservation because the concept of social justice has been overtaken by casteism. His perception is of a highly utopian society which is far from reality and it appears Shri Dwivedi is not a part of the Indian society. I wish his thinking had matched with the mindset of the people of the Indian society which would have made India prosperous and the most powerful country of the world. He is not so ignorant that he does not know that reservation is not for abolition of poverty but to give representation to the weaker castes in governance . Government has separately launched several schemes for abolition of poverty.

In the year 1902, Chhatarpati Sahuji Maharaj, King of Kolhapur State, was the first to announce 50% reservation for Dalits and Backwards. Poona Pact was signed in 1932 and as a consequence, firstly reservation in legislatures was introduced which was followed by reservation in government jobs in the year 1942. The Constituent Assembly gave clearance for reservation which became a part of our Constitution. Does Dwivedi Ji know that reservation of Dalits and Adivasis was there before India became independent. Had he known this fact, then perhaps he would not have made this statement. The system of reservation in Governments and legislatures existing in independent India is more or less the same as was prevalent in British India.

Let us take it that reservation is introduced based on economic factor in which case the well-off people will be the first to get low-income certificate by hook or crook thus to deprive the deserving poor people of their right. This system will have also many flaws. In a country with a population of nearly 125 crore, Government jobs can neither remove property nor a big section of the society can be provided employment. In whichever sector, there is no reservation , the share of Dalits and Backwards is very negligible. Kenneth J. Cooper, Correspondent of American Newspaper Washington Post, wanted to meet a Dalit journalist in New Delhi but was not successful in doing so, as reported by Senior Journalist Shri B.N. Unninyal in Pioneer newspaper. In the film industry, Dalits and Backwards have also no share. If a list of 1000 top industrialists is drawn up, not a single Dalit or Adivasi will be found in the list. There are so many electronic

channels and daily newspapers but not a single channel or newspaper is owned by a Dalit or Adivasi. The share market sector is foreign to Dalits or Adivasis. Privatization of education is taking place at a very fast pace but the share of Dalits and Adivasis here also is very minimal. House building industry, telecommunication , IT sector and the service sector are the backbone of our economy but Dalits and Backwards have hardly any share in these sectors. In the legislatures and Government jobs, the opportunities for development and empowerment are very less.

Rest on Page-6...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Kam